



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 20, 2018/श्रावण 29, 1940

No. 287]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 20, 2018/SHRAVANA 29, 1940

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2018

विषय : मौजूदा उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज), कोल बेड मिथेन (सीबीएम) संविदाओं और नामांकन क्षेत्रों के तहत गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और दोहन के लिए नीतिगत ढांचा।

सं. एक्सप्लो-11019(18)/618/2017-एक्स-1.—भारत सरकार “मौजूदा उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज), कोल बेड मिथेन (सीबीएम) संविदाओं और नामांकन क्षेत्रों के तहत गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और दोहन के लिए नीतिगत ढांचे” को निम्नानुसार एतद्वारा द्वारा अधिसूचित करती है :—

1. पीएससी व्यवस्था (एनईएलपी पूर्व और एनईएलपी)

सरकार ने निम्नलिखित शर्तों पर एनईएलपी पूर्व (नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति) और एनईएलपी उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज) के तहत मौजूदा रकबों में शेल तेल और गैस तथा सीबीएम सहित गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और दोहन की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है : -

(क) संविदाकार को पीएससी की मौजूदा संविदात्मक शर्तों के तहत गैर-परंपरागत हाइड्रोकार्बन्स का अन्वेषण और दोहन करने की अनुमति होगी। पीएससी में संगत शर्तों के घटकों को, जैसा भी मामला हो, आशोधित किया गया माना जाएगा ताकि संविदाकार को संविदा के तहत गैर-परंपरागत हाइड्रोकार्बन्स का दोहन करने की अनुमति दी जा सके।

(ख) अन्वेषण, विकास और उत्पादन पर बहन की गई लागतों की लागत वसूली नई वाणिज्यिक खोजों से उत्पादित पेट्रोलियम और बचाए गए कुल मूल्य से अलग से सुनिश्चित की जाएगी। मौजूदा पीएससीज के तहत सरकार के साथ साझा किए गए लाभ पेट्रोलियम के प्रतिशत के अतिरिक्त, नई खोजों के लिए लाभ पेट्रोलियम सरकार का हिस्सा 10 प्रतिशत होगा। अतिरिक्त 10 प्रतिशत लाभ पेट्रोलियम के अलावा, अन्य सभी राजकोषीय निबंधन एवं शर्तें वही होंगी जो मौजूदा पीएससीज की हैं। लागत वसूली उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश लागू किए जा सकते हैं:

i. नई खोज अथवा खोजों के क्लस्टर की वाणिज्यिक और तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता को स्टैंड एलॉन आधार पर सिद्ध किया जाना चाहिए।

ii. अन्वेषण, विकास और उत्पादन से संबंधित खोजों की सभी लागतों को सुनिश्चित किया जाएगा। सभी व्यय और इससे सृजित राजस्व का पीएससी के लिए उपलब्ध कराई गई लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार अलग से दस्तावेज तैयार किया जाएगा।

(ग) विभिन्न भुगतानों जैसे कि करों, उगाहियों, उप कर, रायल्टी, लाभ हिस्सा आदि के संबंध में पीएससी की निबंधन एवं शर्तें गैर-परंपरागत हाइड्रोकार्बन्स के उत्पादन के लिए भी लागू होंगी।

(घ) दोहरे उद्देश्य वाले कूपों के लिए लागत वसूली और सृजित राजस्व की पद्धति और लेखांकन को डीजीएच द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा। दोहरे उद्देश्य वाले कूप वे कूप होंगे जिनमें गैर-परंपरागत वेधन परंपरागत कूपों में किया जाता है।

(ङ) यदि वाणिज्यिकता की घोषणा (डीओसी) अथवा क्षेत्र विकास योजना (एफडीपी) को प्रस्तुत करते समय, नई हाइड्रोकार्बन खोज अथवा खोजों का कलस्टर स्टैंड एलॉन आधार पर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं होता है तो संविदाकार को इसे विकसित करने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि नई खोज अथवा खोजों के कलस्टर की अन्वेषण से लेकर उत्पादन तक का समग्र पेट्रोलियम प्रचालन सुनिश्चित किया गया हो। इस प्रकार की खोजों से लागतों और राजस्व को सुनिश्चित किया जाएगा और इससे पूर्व में सुनिश्चित खोजों सहित पहले से मौजूद खोजों से सृजित लाभ पेट्रोलियम के सरकार के हिस्से पर कभी भी कोई प्रभाव नहीं होगा।

2. सीबीएम संविदाएं :

सरकार ने निम्नलिखित शर्तों पर मौजूदा सीबीएम संविदाओं में शेल तेल/गैस सहित तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के तहत सभी प्रकार के हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और दोहन की अनुमति देने का निर्णय लिया है :—

- i. पीईएल/पीएमएल में संशोधन की मंजूरी के बाद सीबीएम संविदाकार को परंपरागत और गैर-परंपरागत हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि शेल गैस और तेल तथा इसके साथ ही सीबीएम का अन्वेषण और दोहन करने की अनुमति होगी। यह मान लिया जाएगा कि सीबीएम संविदाओं में संबंधित शर्तों की विषय-वस्तु को संशोधित कर दिया गया है।
- ii. संविदाकार द्वारा संविदा के तहत उत्पादित शेल गैस/तेल अथवा अन्य हाइड्रोकार्बन्स के संबंध में मौजूदा सीबीएम संविदा में यथा विनिर्दिष्ट सीबीएम के लिए पीएलपी प्रतिशत के अतिरिक्त 10 प्रतिशत का अतिरिक्त उत्पादन स्तर भुगतान (पीएलपी) का किया जाना अपेक्षित होगा।
- iii. सीबीएम संविदा में शेल तेल उत्पादन के मामले में, रायल्टी आदि के भुगतान के प्रयोजनार्थ तेल को ऊर्जा के अर्थ में गैस की मात्रा के तुल्य में परिवर्तित किया जाएगा। इस्तेमाल किए जाने वाले परिवर्तन का पैमाना 1 मिलियन बैरल तेल 160.25 एमएमएससीएम गैस के बराबर होगा।

3. पीएससी और सीबीएम संविदाओं के लिए सामान्य निबंधन और शर्तें:

- i. संशोधित पीएससी और सीबीएम संविदाओं के तहत पट्टा अवधि के निबंधन और शर्तें मूल पीएससी और सीबीएम संविदा के साथ समवर्ती चलेंगी।
- ii. ढांचागत स्थायित्व और कोयला दरारों के संरक्षण तथा पीएससी व्यवस्था के मौजूदा रकबों में सीबीएम के निष्कासन के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) और कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक परामर्शदात्री और समन्वय व्यवस्था 23 सितम्बर, 1997 को कोयला मंत्रालय में हस्ताक्षरित एमओयू के क्रम में विकसित की जाएगी।
- iii. यह नीति पीएससी के सभी प्रचालनात्मक ब्लाकों और सीबीएम व्यवस्था पर लागू होगी। तथापि, यह ऐसे ब्लाकों पर लागू नहीं होगी जहां संविदाकार त्याग के लिए पहले ही आवेदन कर चुका है या ब्लाक समाप्ति की कार्यवाई के तहत है या जहां इस नीति की अधिसूचना की तारीख को कानूनी कार्यवाई चल रही है।
- iv. इस नीति में अन्यथा प्रदत्त को छोड़कर, पीएससी और सीबीएम संविदाओं के मौजूदा निबंधन और शर्तें शेल गैस/तेल, सीबीएम या अन्य सभी हाइड्रोकार्बन्स का अन्वेषण और दोहन करते समय लागू होंगी।

4. नामांकन व्यवस्था

नेशनल ऑयल कंपनियों (एनओसीज) को दिए गए नामांकन ब्लॉकों में, एनओसीज को एनओसीज को नामांकन रकबों के तहत प्रदान किए गए पीईएल/पीएमएल की मौजूदा राजकोषीय संविदात्मक शर्तों के अनुसार तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 मौजूदा राजकोषीय और पीईएल/पीएमएल तहत शेल तेल और गैस सहित गैर परम्परागत हाइड्रोकार्बन्स के अन्वेषण और दोहन की अनुमति होगी। शेल गैस नीति, 2013 उस सीमा तक संशोधित और बढ़ा दी गई समझी जाएगी।

5. सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएस) :

सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, वित्त सचिव, विधि सचिव तथा सचिव, व्यय विभाग को शामिल करते हुए गठित की गई सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएस) को इस नीति के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाले प्रचालनात्मक मुद्दों का समाधान करने का कार्य सौंपा गया है।

अमर नाथ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2018

POLICY FRAMEWORK FOR EXPLORATION AND EXPLOITATION OF UNCONVENTIONAL HYDROCARBONS UNDER EXISTING PRODUCTION SHARING CONTRACTS (PSCs), COAL BED METHANE (CBM) CONTRACTS AND NOMINATION FIELDS

No. Expl-11019(18)/618/2017-Exp-1.—The Government of India hereby notifies “Policy framework for exploration and exploitation of unconventional hydrocarbons under existing Production Sharing Contracts (PSCs), Coal Bed Methane (CBM) contracts and Nomination Fields” as hereunder:

1. PSC regime (Pre-NELP and NELP)

The Government has decided to permit exploration and exploitation of unconventional hydrocarbons, including shale oil and gas and CBM in existing acreages under Pre-NELP (New Exploration Licencing Policy) and NELP Production Sharing Contracts (PSCs) subject to following terms and conditions:

- a. The Contractor will be allowed to explore and exploit unconventional hydrocarbons under existing contractual terms of the PSC. The contents of the relevant clauses in the PSC, as the case may be, will be deemed to have been modified to permit the Contractor to exploit unconventional hydrocarbons under the Contract.
- b. There will be separate ring-fencing for cost recovery of cost incurred on exploration, development and production from the total value of petroleum produced and saved from new commercial discoveries. The Government share of Profit Petroleum for new discoveries will be 10% over and above the percentage of Profit Petroleum shared with the Government under existing PSCs. Except additional 10% Profit Petroleum, all other fiscal terms and conditions will be that of existing PSCs. Following guidelines may be applied for cost recovery purposes:
 - i. The commercial and techno-economical viability of new discovery or cluster of discoveries will be established on standalone basis.
 - ii. All costs of discoveries related to exploration, development and production will be ring-fenced. All expenditure and revenue generated thereof will be documented separately in accordance with the Accounting Procedure provided for the PSC.
- c. The terms and conditions of the PSC in respect of various payments such as taxes, levies, Cess, Royalty and Profit Share etc. shall be applicable to production of unconventional hydrocarbons also.
- d. The methodology and accounting of costs recovery and revenues generated for dual purpose wells will be notified by DGH separately. Dual purpose wells will be those wells where drilling of unconventional is conducted in the conventional wells.

- e. In cases where at the time of submitting Declaration of Commerciality (DoC) or Field Development Plan (FDP), new hydrocarbon discovery or cluster of discoveries is not commercially viable on standalone basis, Contractor may be permitted to develop the same provided the entire Petroleum Operations from exploration to production of new discovery or cluster of discoveries is ring-fenced. The costs and revenues from such discoveries will be ring-fenced and will not have any impact whatsoever on the Government share of Profit Petroleum generated from already monetized discoveries including earlier ring-fenced discoveries.

2. CBM Contracts:

The Government has decided to permit exploration and exploitation of all types of hydrocarbons under the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, including Shale oil/gas in the existing CBM contracts subject to following terms and conditions:

- i. CBM Contractor will be allowed to explore and exploit conventional and unconventional hydrocarbons such as Shale gas and oil along with CBM after grant of modified PEL/PML. The contents of relevant clauses in CBM Contracts will be deemed to have been modified.
- ii. The Contractor will be required to pay additional Production Level Payment (PLP) of 10% over and above the PLP percentage for CBM as specified in the existing CBM Contract, in respect of the Shale gas /oil or other hydrocarbons produced under the Contract.
- iii. In the case of Shale oil production in CBM contract, oil will be converted into equivalent gas volume in energy terms for the purpose of payment of royalty etc. The conversion scale used will be 1 million barrel of oil equivalent to 160.25 MMSCM of gas.

3. Common Terms and Conditions for the PSCs and CBM contracts:

- i. The terms and conditions of the lease period under amended PSCs and CBM contracts would run concurrent with the original PSC and CBM Contract.
- ii. For structural stability and conservation of coal seams, and extraction of CBM in existing acreages of PSC regime, a consultative and coordination mechanism comprising of representatives of Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoP&NG) and Ministry of Coal will be developed in continuation of MoU signed with Ministry of Coal on 23rd September, 1997.
- iii. This policy will be applicable to all operational blocks of PSC and CBM regime. However, it would not apply to blocks where Contractor has already applied for relinquishment or blocks under termination proceedings or where arbitration or legal proceedings are going on as on the date of notification of this policy.
- iv. Except as otherwise provided in this Policy, the existing terms and conditions of the PSC and CBM contracts will be applicable while exploring and exploiting Shale Gas/Oil, CBM or all other hydrocarbons.

4. Nomination Blocks

In nomination blocks, given to National Oil Companies (NOCs), the NOCs will be allowed to explore and exploit of all types of hydrocarbons under the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959 as per existing fiscal and contractual terms of PEL/PML granted under nomination acreages. The Shale Gas Policy of 2013 will be deemed to be modified and/or extended to that extent.

5. Empowered Committee of Secretaries (ECS):

An Empowered Committee of Secretaries (ECS) comprising of Secretary, Petroleum and Natural Gas, Finance Secretary, Law Secretary and Secretary, Department of Expenditure is entrusted with the function of resolving operational issues arising during the implementation of this policy.

AMAR NATH, Jt. Secy.